Daily Current Affairs
06 June 2025

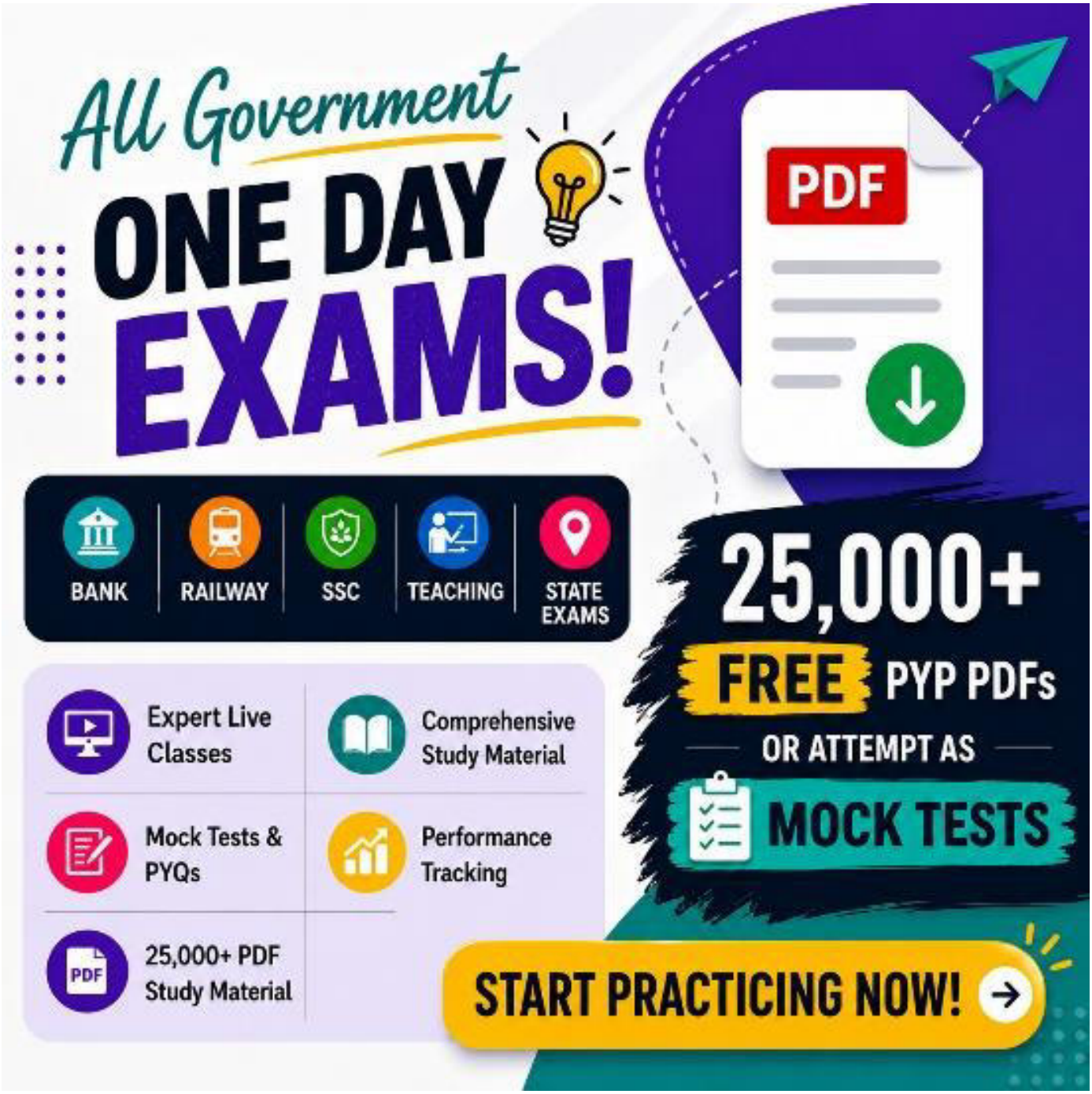

Daily Current Affairs Quiz 06 June 2026

Q1. राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में "गरीबी मुक्त & उन्नत आजीविका पंचायत" श्रेणी के तहत किस ग्राम पंचायत ने रैंक 1 हासिल की?

(a) मुद्राडी

(b) चेम्मुलपल्ली

(c) ग्यालशिंग ओमचुंग

(d) वंडसे

Ans.(a)

Sol. सही उत्तर (A) मुद्राडी है

व्याख्या:

• राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के तहत, कर्नाटक के उडुपी जिले के हेब्री तालुक में स्थित मुद्राडी ग्राम पंचायत ने 'गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका पंचायत' के महत्वपूर्ण विषय के तहत देश भर में प्रतिष्ठित रैंक 1 हासिल की है।

• दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार (DDUPSVP) श्रेणी के तहत इस उल्लेखनीय सम्मान के साथ ₹1 करोड़ की पर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहन राशि दी गई, जिसका उद्देश्य स्थानीय निकाय को अपने अधिकार क्षेत्र में आगे के सतत विकास और पूंजीगत कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम बनाना है।

• राष्ट्रीय स्तर पर मुद्राडी ग्राम पंचायत का चयन इसके असाधारण सामाजिक-आर्थिक प्रदर्शन मेट्रिक्स, विशेष रूप से ग्रामीण परिवारों के लिए सामुदायिक लामबंदी और आजीविका विविधीकरण के इसके अत्यधिक प्रभावी मॉडल द्वारा प्रेरित था।

• पंचायत ने 650 से अधिक स्थानीय महिलाओं को 65 जीवंत स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में सफलतापूर्वक एक साथ लाया, 100% औपचारिक बैंक ऋण लिंकेज सुनिश्चित किया और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ₹100 लाख से अधिक के वार्षिक ऋण उपयोग को पार किया।

• इसके अलावा, मुद्राडी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) का दोषरहित कार्यान्वयन प्रदर्शित किया, 28,500 से अधिक मानव-दिवस का कार्य उत्पन्न किया, 128 कमजोर परिवारों को पूर्ण रोजगार के 100 दिनों की गारंटी दी, और पूर्ण नल जल कनेक्टिविटी के साथ-साथ सामाजिक कल्याण पेंशन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) कवरेज में 100% सार्वभौमिक संतृप्ति प्राप्त की।

Information Booster:

• महत्वपूर्ण रूप से, मुद्राडी ग्राम पंचायत का नेतृत्व सक्रिय रूप से एक महिला निर्वाचित प्रमुख/सरपंच द्वारा किया जाता है, जो भारत के ग्रामीण परिदृश्य में संरचनात्मक प्रशासनिक सफलता और पारदर्शिता को चलाने में महिला नेतृत्व की विस्तारित और प्रभावशाली भूमिका को उजागर करता है।

• 'गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका' विषय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुकूलित नौ स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों (LSDGs) के बीच पहला मूलभूत स्तंभ है, ताकि गांव स्तर पर अत्यधिक गरीबी को व्यवस्थित रूप से समाप्त किया जा सके और आय-सृजन के लचीले अवसर पैदा किए जा सकें।

Additional Knowledge:

• चेम्मुलपल्ली (विकल्प B): चेम्मुलपल्ली ग्राम पंचायत आंध्र प्रदेश के वाई.एस.आर. (कडप्पा) जिले के खाजीपेट ब्लॉक में स्थित है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में, इसने उसी 'गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका पंचायत' श्रेणी के तहत राष्ट्रीय रैंक 2 हासिल करने के लिए असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे इसे ₹75 लाख की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई। हालांकि यह ग्रामीण उत्कृष्टता के एक मॉडल के रूप में खड़ा है, इसे मुद्राडी के ठीक पीछे रखा गया था।

• ग्यालशिंग ओमचुंग (विकल्प C): ग्यालशिंग ओमचुंग ग्राम पंचायत सिक्किम के ग्यालशिंग जिले में स्थित है। जमीनी स्तर के शासन के प्रति हिमालयी क्षेत्र के समर्पण का प्रतिनिधित्व करते हुए, इस पंचायत ने 'गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका पंचायत' विषयगत क्षेत्र में राष्ट्रीय रैंक 3 हासिल की, जिससे इसके अद्वितीय पर्वतीय आजीविका मॉडल और जैविक खेती के एकीकरण के लिए ₹50 लाख का पुरस्कार अर्जित किया।

• वंडसे (विकल्प D): वंडसे ग्राम पंचायत कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुरा तालुक में स्थित एक और अत्यधिक सफल स्थानीय निकाय है। एक महिला सरपंच के नेतृत्व में, इसने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में एक पूरी तरह से अलग विषय—'स्वस्थ पंचायत' श्रेणी—के तहत राष्ट्रीय रैंक 2 हासिल करके अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिसके लिए इसे अपने उत्कृष्ट सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा पहुंच और स्वच्छता मॉडल के कारण ₹75 लाख का नकद पुरस्कार मिला।

Q2. राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त किए?

(a) आंध्र प्रदेश

(b) ओडिशा

(c) कर्नाटक

(d) तमिलनाडु

Ans.(c)

Sol. सही उत्तर (C) कर्नाटक है

व्याख्या:

• राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए हाल ही में घोषित परिणामों में, कर्नाटक राज्य प्रतिष्ठित दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार (DDUPSVP) श्रेणी के तहत कुल छह राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करके देश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक के रूप में उभरा।

• पूरे देश में चुनी गई 42 उत्कृष्ट पंचायतों में से, कर्नाटक ने अकेले छह पुरस्कार जीते, जो ग्रामीण कल्याण योजनाओं, स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास और जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक प्रथाओं को लागू करने में इसके बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है।

• उल्लेखनीय रूप से, कर्नाटक में छह पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायतों में से पांच एक ही जिले के हैं, जो उडुपी जिला है, जो क्षेत्र के भीतर ग्रामीण शासन में उत्कृष्टता का एक असाधारण क्लस्टर मॉडल प्रदर्शित करता है।

• कर्नाटक से जीतने वाली ग्राम पंचायतों में मुद्राडी ग्राम पंचायत (गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका के तहत पहली रैंक हासिल की), वंडसे ग्राम पंचायत (स्वस्थ पंचायत के तहत दूसरी रैंक हासिल की), बेंगलुरु शहरी में हलनायकानहल्ली ग्राम पंचायत (बाल-अनुकूल पंचायत के तहत दूसरी रैंक हासिल की), मदमक्की ग्राम पंचायत (जल-पर्याप्त पंचायत के तहत दूसरी रैंक हासिल की), सानूर ग्राम पंचायत (आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे के तहत तीसरी संयुक्त रैंक हासिल की), और हकलाडी ग्राम पंचायत (सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत के तहत तीसरी संयुक्त रैंक हासिल की) शामिल हैं।

• यह शानदार उपलब्धि कर्नाटक के मजबूत विकेन्द्रीकृत प्रशासनिक ढांचे और इसके पंचायती राज विभागों के तहत सक्रिय सामुदायिक भागीदारी को उजागर करती है, जो इसे राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रक्रिया में अन्य प्रमुख राज्यों से आगे रखती है।

Information Booster:

• कुल मिलाकर भारत के दक्षिणी राज्यों ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 चक्र के दौरान उल्लेखनीय शासन प्रभुत्व प्रदर्शित किया, और देश भर में वितरित कुल 42 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से 18 सामूहिक रूप से प्राप्त किए।

• 6 पुरस्कारों के साथ कर्नाटक के नेतृत्व के बाद, आंध्र प्रदेश और ओडिशा भी प्रमुख विजेताओं के रूप में सामने आए, जिन्होंने अपने संबंधित स्थानीय निकायों के लिए 5-5 राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किए।

• इसके विपरीत, उत्तरी हिंदी भाषी क्षेत्र के कुछ अत्यधिक आबादी वाले राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश (जिसमें भारत में सबसे अधिक पंचायतें हैं) और बिहार, ने केवल 1-1 राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया, जो केंद्रीय मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन किए गए मेट्रिक्स में पर्याप्त प्रदर्शन असमानता को उजागर करता है।

Additional Knowledge:

• आंध्र प्रदेश (विकल्प A): आंध्र प्रदेश 5 राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर सबसे आगे रहने वाले राज्यों में से एक था। राज्य की प्रमुख विजेता पंचायतों में चेम्मुलपल्ली ग्राम पंचायत शामिल है, जिसने गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका विषय में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया, और शृंगवरम ग्राम पंचायत, जो सुशासन वाली पंचायत श्रेणी के तहत देश में शीर्ष पर रही। यद्यपि यह अत्यधिक सफल रहा, लेकिन इसकी संख्या कर्नाटक से ठीक पीछे थी।

• ओडिशा (विकल्प B): ओडिशा ने 5 राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर ग्रामीण परिवर्तन में असाधारण प्रदर्शन का प्रदर्शन किया। इसके स्थानीय निकायों ने सामाजिक सुरक्षा वितरण, स्वच्छ और हरित पहलों और जल प्रबंधन में जबरदस्त सुधार प्रदर्शित किया। उदाहरण के लिए, ओडिशा में गंजम जिला पंचायत को नानाजी देशमुख श्रेणी के तहत भारत में दूसरी सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में मान्यता दी गई थी। हालांकि, इसका कुल योग कर्नाटक के 6 पुरस्कारों से कम था।

• तमिलनाडु (विकल्प D): तमिलनाडु को ग्राम समितियों (जैसे उथिरमेरूर शिलालेख) में अपनी ऐतिहासिक जड़ों और आधुनिक सामाजिक-आर्थिक कल्याण मॉडल के लिए मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में, इसने नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के तहत एक बड़ी जीत हासिल की, जहां कोयंबटूर जिला पंचायत को पूरे देश में तीसरी सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में स्थान दिया गया। इस उच्च-स्तरीय संस्थागत मान्यता के बावजूद, इसके कुल पुरस्कारों की संख्या कर्नाटक से कम थी।

Q3. DDUPSVP पुरस्कार किस सूचकांक से जुड़े हैं?

(a) मानव विकास सूचकांक

(b) पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) 2.0

(c) सतत शासन सूचकांक

(d) जीवन सुगमता सूचकांक

Ans.(b)

Sol. सही उत्तर (B) पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) 2.0 है

व्याख्या:

• दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार (DDUPSVP) पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) 2.0 नामक नए उन्नत और परिष्कृत डेटा-संचालित ढांचे से व्यवस्थित रूप से जुड़े हुए हैं और इसके माध्यम से मूल्यांकन किए जाते हैं।

• केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी, पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) 2.0 देश भर में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय रिपोर्ट कार्ड के रूप में कार्य करता है, जो मजबूत, अनुभवजन्य डेटा के माध्यम से उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।

• PAI 2.0 विशेष रूप से यह मापता है कि स्थानीय ग्रामीण निकाय सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (LSDGs) से जुड़े नौ मुख्य विकास विषयों को कितनी प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। इनमें गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ और हरे-भरे गांव, बाल कल्याण और बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।

• उन्नत PAI 2.0 ढांचे के तहत, मूल्यांकन कार्यप्रणाली 150 ठोस संकेतकों और 230 अलग-अलग डेटा बिंदुओं पर ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन करती है। यह PAI 1.0 की तुलना में एक अत्यधिक सुव्यवस्थित और तर्कसंगत संस्करण है, जिसमें 516 संकेतकों और 794 डेटा बिंदुओं का एक अत्यधिक जटिल ढांचा था, जिससे मूल्यांकन अधिक केंद्रित, उपयोगी और सीधे राष्ट्रीय योजना संरचनाओं के साथ संरेखित हो गया है।

• उनके समग्र PAI 2.0 स्कोर के आधार पर, भाग लेने वाली पंचायतों को अचीवर (90 और उससे अधिक का A+ स्कोर), फ्रंट रनर (75 से 90 से कम का A स्कोर), परफॉर्मर (60 से 75 से कम का B स्कोर), एस्पिरेंट (40 से 60 से कम का C स्कोर), से लेकर बिगिनर (40 से कम का D स्कोर) तक के अलग-अलग प्रदर्शन ग्रेड में पारदर्शी रूप से वर्गीकृत किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए वस्तुनिष्ठ बेंचमार्किंग की अनुमति मिलती है।

Information Booster:

• PAI 2.0 ने अभूतपूर्व जमीनी स्तर के डेटा पैठ को प्राप्त किया है, 97.30 प्रतिशत की उल्लेखनीय राष्ट्रीय भागीदारी दर दर्ज की है, जिसमें 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 2,59,867 ग्राम पंचायतों ने केंद्रीय पोर्टल पर अपने प्रशासनिक डेटा को सफलतापूर्वक मान्य और प्रस्तुत किया है।

• नवीनतम PAI 2.0 रिपोर्ट से पता चला है कि राष्ट्रव्यापी 3,635 ग्राम पंचायतें सफलतापूर्वक 'फ्रंट रनर' के रूप में उभरी हैं, जबकि 1,18,824 ग्राम पंचायतें 'परफॉर्मर' श्रेणी में आगे बढ़ी हैं, जिसमें आजीविका संवर्धन और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में सबसे मजबूत सकारात्मक प्रगति दर्ज की गई है।

Additional Knowledge:

• मानव विकास सूचकांक (विकल्प A): मानव विकास सूचकांक (HDI) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त एक समग्र सूचकांक है। यह मानव विकास के तीन बुनियादी आयामों में दीर्घकालिक राष्ट्रीय प्रगति को मापता है: एक लंबा और स्वस्थ जीवन (जीवन प्रत्याशा), ज्ञान तक पहुंच (शिक्षा), और जीवन का एक सभ्य स्तर (प्रति व्यक्ति GNI)। यह देश/मैक्रो स्तर पर कार्य करता है और इसका उपयोग DDUPSVP के लिए व्यक्तिगत भारतीय पंचायतों का मूल्यांकन करने के लिए नहीं किया जाता है।

• सतत शासन सूचकांक (विकल्प C): सतत शासन सूचकांक (SGI) OECD और EU देशों के बीच नीतिगत प्रदर्शन और शासन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए बर्टेल्समन स्टिफ्टंग जैसे संगठनों द्वारा विकसित एक अंतरराष्ट्रीय क्रॉस-नेशनल निगरानी और बेंचमार्किंग टूल है। भारत सरकार द्वारा प्रबंधित स्थानीय निकायों या ग्रामीण शासन ढांचे के लिए इसकी कोई संरचनात्मक या संस्थागत प्रासंगिकता नहीं है।

• जीवन सुगमता सूचकांक (विकल्प D): जीवन सुगमता सूचकांक भारत में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा डिज़ाइन और कार्यान्वित एक मूल्यांकन उपकरण है। यह शहरों को रैंक करने के लिए जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिक धारणा जैसे मापदंडों में शहरी केंद्रों और नगर निगमों का मूल्यांकन करता है। यह ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं के बजाय विशेष रूप से शहरी आवासों पर केंद्रित है।

Q4. राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के तहत प्रदान की जाने वाली अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन राशि क्या है?

(a) ₹1 करोड़

(b) ₹2 करोड़

(c) ₹3 करोड़

(d) ₹5 करोड़

Ans.(d)

Sol. सही उत्तर (D) ₹5 करोड़ है

व्याख्या:

• राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, एकल विजेता स्थानीय निकाय को दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन राशि ₹5 करोड़ तक पहुंचती है।

• ₹5 करोड़ की यह अधिकतम पुरस्कार राशि विशेष रूप से नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार (NDSPSVP) श्रेणी के तहत सबसे शीर्ष विजेताओं के लिए आरक्षित है, जो समग्र विकास और संस्थागत शासन उत्कृष्टता के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली जिला पंचायतों (जिला परिषदों) को मान्यता देता है।

• उदाहरण के लिए, 2025 के पुरस्कार चक्र में, त्रिपुरा राज्य में स्थित सिपाहीजला जिला पंचायत ने भारत में सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में रैंक 1 स्थान हासिल किया, जिससे अपने बड़े पैमाने पर ग्रामीण विकास कार्यों को और बढ़ाने के लिए ₹5 करोड़ का पूर्ण वित्तीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

• इन पुरस्कारों के तहत वितरित वित्तीय प्रोत्साहन केंद्र सरकार की प्रमुख योजना—राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत 'पंचायतों को प्रोत्साहन' (IoP) घटक द्वारा शासित होते हैं। विजेता पंचायतों द्वारा धन का उपयोग स्थायी स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास, सार्वजनिक संपत्ति वितरण में सुधार और महत्वपूर्ण विकासात्मक अंतराल को भरने के लिए सख्ती से अनिवार्य है।

• वित्तीय प्रोत्साहन का पैमाना स्तरों और पदों के अनुसार पदानुक्रमित रूप से भिन्न होता है, जो ग्राम पंचायत स्तर पर तीसरे स्थान के संयुक्त विजेताओं के लिए ₹25 लाख से लेकर जिला स्तर पर प्रथम स्थान के विजेताओं के लिए ₹5 करोड़ तक होता है, जो स्थानीय निकायों के लिए एक असाधारण रूप से शक्तिशाली राजकोषीय प्रेरणा पैदा करता है।

Information Booster:

• दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार (DDUPSVP) श्रेणी के तहत, जो नौ अलग-अलग विषयगत लक्ष्यों में विशेष रूप से व्यक्तिगत ग्राम पंचायतों पर लक्षित है, सर्वोच्च वित्तीय पुरस्कार ₹1 करोड़ है, जो प्रत्येक विषय के प्रथम-रैंक धारक को दिया जाता है (जैसे गरीबी उन्मूलन के लिए मुद्राडी जीपी या स्वास्थ्य के लिए कंचनबाड़ी जीपी)।

• DDUPSVP श्रेणी के तहत दूसरे रैंक धारकों को ₹75 लाख मिलते हैं, जबकि तीसरे रैंक धारकों को आम तौर पर ₹50 लाख या ₹25 लाख (संयुक्त रैंकिंग के मामले में) मिलते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ग्राम स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन को अच्छी तरह से पुरस्कृत किया गया है।

• नानाजी देशमुख श्रेणी के तहत उच्च-स्तरीय स्थानीय निकायों के लिए, दूसरे स्थान पर रहने वाली जिला पंचायत को ₹3 करोड़ का नकद पुरस्कार मिलता है (2025 के लिए ओडिशा में गंजम द्वारा जीता गया), और तीसरे स्थान पर रहने वाली जिला पंचायत को ₹2 करोड़ मिलते हैं (2025 के लिए तमिलनाडु में कोयंबटूर द्वारा जीता गया)।

Additional Knowledge:

• ₹1 करोड़ (विकल्प A): जबकि ₹1 करोड़ स्थानीय विकास के लिए एक बड़ी राशि का प्रतिनिधित्व करता है, यह संपूर्ण पुरस्कार प्रणाली की पूर्ण अधिकतम वित्तीय सीमा नहीं है। इसके बजाय, ₹1 करोड़ नौ विशेष स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों (LSDGs) विषयों में से प्रत्येक के तहत स्थानीय शासन के सबसे निचले स्तर, अर्थात ग्राम पंचायतों में रैंक 1 के विजेताओं को विशेष रूप से आवंटित अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन है।

• ₹2 करोड़ (विकल्प B): ₹2 करोड़ का वित्तीय आंकड़ा रणनीतिक रूप से उच्च स्तरों के मध्यवर्ती इनाम कोष्ठक के भीतर स्थित है। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के तहत, ₹2 करोड़ का नकद प्रोत्साहन उस जिला पंचायत को प्रदान किया जाता है जो देश भर में राष्ट्रीय रैंक 3 स्थान हासिल करती है, जैसा कि 2025 चक्र में कोयंबटूर जिला पंचायत के साथ देखा गया था।

• ₹3 करोड़ (विकल्प C): विचलन के उच्चतम स्तर पर राष्ट्रीय रैंक 2 स्थान हासिल करने वाले स्थानीय निकाय को ₹3 करोड़ का नकद प्रोत्साहन दिया जाता है, जो नानाजी देशमुख श्रेणी के तहत जिला पंचायत स्तर है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में, ओडिशा की गंजम जिला पंचायत ने इस रैंक को सफलतापूर्वक हासिल किया और अपने असाधारण प्रशासनिक ट्रैक रिकॉर्ड के लिए ₹3 करोड़ की पुरस्कार राशि प्राप्त की।

Q5. राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के तहत किन नेताओं की जोड़ी के नाम पर पंचायत पुरस्कारों का नाम रखा गया है?

(a) महात्मा गांधी और विनोबा भावे

(b) दीन दयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख

(c) अटल बिहारी वाजपेयी और दीन दयाल उपाध्याय

(d) जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख

Ans.(b)

Sol. सही उत्तर (B) दीन दयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख है

व्याख्या:

• पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, जमीनी स्तर के विकास को आगे बढ़ाने और स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों (LSDGs) को प्राप्त करने में देश भर में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के अनुकरणीय प्रदर्शन का सम्मान करने के लिए वार्षिक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करता है।

• राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के तहत, पुरस्कारों को प्रमुख नेताओं के नाम पर दो प्राथमिक व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है: दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार (DDUPSVP) और नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार (NDSPSVP)।

• दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार (DDUPSVP) विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (LSDGs) के नौ पूर्व-निर्धारित विषयगत क्षेत्रों, जैसे गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, बाल अनुकूलता और लैंगिक समानता में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन और पुरस्कार देता है। 2025 के पुरस्कारों के लिए, 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 34 ग्राम पंचायतों को इस श्रेणी के तहत चुना गया था।

• दूसरी ओर, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार (NDSPSVP) पंचायती राज प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर सभी विकास विषयों में पंचायतों की समग्र उत्कृष्टता को मान्यता देता है, जिसमें जिला पंचायतें (जिला परिषद), ब्लॉक पंचायतें (पंचायत समितियां) और ग्राम पंचायतें शामिल हैं। 2025 के पुरस्कार चक्र में, इस शीर्ष स्तर की उत्कृष्टता के लिए 8 उत्कृष्ट पंचायतों का चयन किया गया था।

• एक साथ, इन दोनों श्रेणियों का उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय निकायों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करना, साक्ष्य-आधारित योजना को प्रोत्साहित करना और 'विकसित भारत' (Developed India) प्राप्त करने के व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में ग्रामीण समुदायों को प्रेरित करना है।

Information Booster:

• राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) की केंद्र प्रायोजित योजना के पंचायतों को प्रोत्साहन (IoP) घटक के तहत संस्थागत रूप दिया गया है।

• मूल्यांकन ढांचे में नए उन्नत पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) 2.0 पर आधारित एक अत्यधिक वस्तुनिष्ठ और डेटा-संचालित दृष्टिकोण शामिल है। यह सूचकांक नौ अलग-अलग विकास विषयों में 150 संकेतकों और 230 अलग-अलग डेटा बिंदुओं का उपयोग करता है।

• राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 का एक प्रेरक आकर्षण महिला सशक्तिकरण पर मजबूत जोर है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि देश भर की 42 पुरस्कार विजेता पंचायतों में से 22 का नेतृत्व सक्रिय रूप से महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जो समावेशी शासन की दिशा में एक स्मारकीय बदलाव को दर्शाता है।

Additional Knowledge:

• महात्मा गांधी और विनोबा भावे (विकल्प A): महात्मा गांधी ने 'ग्राम स्वराज' (ग्राम स्वशासन) की दृढ़ता से वकालत की, गांवों को भारतीय लोकतंत्र की मूलभूत इकाइयों के रूप में देखा। आचार्य विनोबा भावे ने स्वैच्छिक भूमि सुधार और ग्रामीण समानता लाने के लिए भूदान आंदोलन की शुरुआत की। हालांकि दोनों ग्रामीण सशक्तिकरण और विकेंद्रीकरण के ऐतिहासिक प्रतीक हैं, लेकिन राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 ढांचे के तहत इस विशिष्ट जोड़ी के नाम पर किसी भी पुरस्कार का नाम नहीं रखा गया है।

• अटल बिहारी वाजपेयी और दीन दयाल उपाध्याय (विकल्प C): पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण संपर्क का समर्थन किया। पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद और अंत्योदय (अंतिम व्यक्ति का उत्थान) के दर्शन को तैयार किया। जबकि दीन दयाल उपाध्याय के नाम का उपयोग DDUPSVP के लिए किया जाता है, इन विशिष्ट पुरस्कारों के लिए पूर्व पीएम वाजपेयी का नाम उनके साथ नहीं जोड़ा गया है।

• जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख (विकल्प D): जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकप्रिय रूप से जेपी के नाम से जाना जाता है, एक प्रतिष्ठित नेता थे जिन्होंने संपूर्ण क्रांति और विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक भागीदारी की वकालत की थी। नानाजी देशमुख एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन के बाद का समय ग्रामीण परिवर्तन, विशेष रूप से चित्रकूट क्षेत्र में, ग्रामीण समूहों में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास करने के लिए समर्पित कर दिया। हालांकि वे करीबी वैचारिक सहयोगी थे, वर्तमान राष्ट्रीय पुरस्कार संरचना जेपी और नानाजी के बजाय पंडित दीन दयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख को जोड़ती है।